परियोजनाओं का राज्यों को हस्तांतरण

1056. **श्री अजीत जोगी** :

श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) राज्यों को हस्तांतरित की जा रही योजनाओं और उनके अंतर्गत राज्यों, विशेषकर मध्य-प्रदेश को दी जा रही राशि का राज्य-वारा ब्यौरा क्या है,

(ख) धनराशि जारी किए जाने में विलम्ब के क्या कारण है,

(ग) हस्तांतरण के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और संबधित कार्य के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेश्वर सावनूर): (क) से (ग) परियोजनाओं का राज्यों को हंस्तारित किए जाने को कोई प्रस्ताव नहीं हैं । यद्यपि योजना आयोग में केन्द्र रूप में प्रायोजित स्कीमों के राज्यों को हस्तांरित करने का प्रयोग किया गया हैं। संबधित केन्दीय मंत्रालयों /विभागों और सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को टिप्पणियों हेतु एक नोट भिजवाया गया है । उसके प्राप्त होने पर पूरे योजना आयोग और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के विचारार्थ एक नोट तैयार किया जाएगा ।t

Adoption of Decentralised Planning

1057. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state;

(a) whether it is a fact that there has been a policy, right from First Five Year Plan, to encourage and adopt decentralised planning;

(b) if so, what progress has been made during these five decades and to what extent decentralised planning has been implemented;

(c) what inderance have been experienced in effective decentralised planning and what specific action has been taken to overcome them; and

(d) to what extent, village, ground, or micro level workers are competent and equipped to undertake decentralised planning and what action has been taken to make them competent and equip them to function effectively?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRIMATI RATNAMALA DEHARESHWAR SAVANOOR): (a) to (d) Decentralised planning has been advocated in the various Five Year Plans. As a response to demands from different quarters to take planning to the grassroot, level, Government of India have taken a significant step through enactment of the 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts. Pursuart on this States have fulfilled their commitment regarding the constitution of State Election Commissions and State Finance Commissions. The process of devolution of financial and administrative power to the elected local bodies is at various stages of Operationalisation in different States. The local bodies through the institution of DPCs would be responsible for the preparation of plans for economic development and social justice and for their impoelementation. The States have been directed to indicate the resources earmarked for schemes to be implemented by the local bodies in the plans of the States. A network of training institutions at various levels is engaged in training grassroot level functionaries.

Approval on Ninth Plan Approach Paper by NDC

1058. PROF. RAM KAPSE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the National Development Council (NDC) has approved the Approach Paper to the Ninth Five Year Plan; and

(b) if not, by when it is likely to be approved?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRIMATI RATNAMALA DEHARESHWAR SAVANOOR): (a) Yes, Sir. The Approach Paper to the

Ninth Five Year Plan has been approved unanimously by National Development Council in its meeting held on 16.01.1997.

(b) Does not arise.

बेरोजगारी में वृद्धि

1059. **श्री नागमणि** :
श्री ईश दत्त यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
-

(क) क्या यह सच है कि देश में उत्पादकता में गिरावट के कारण बेरोजगारी की संख्या तेजी से बढ़ रही है,

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस समस्या के निरकारण हेतु क्या-क्या प्रयास किए हैं, और

(ग) यदि कोई प्रयास नहीं किए गए हैं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना और कार्यक्रम कायान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेश्वर सावनूर) : (क) से (ग) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए रोजगार और बेरोजगारी पर पंचवार्षीक नमूना सर्वेक्षण-सामान्य सिद्धांत स्थिति (यूपीएस) के अनुसार बेरोजगार व्यक्तियों के अनुमान 1987-88 (43वें दौर) में 11.53 मिलियन व्यक्तियों से घटकर 1993-94 (50वें दौर) में 8.93 मिलियन व्यक्ति हो गए हैं ।

नौंवी योजना के दृष्टिकोण में उत्पादक रोजगार को प्राथमिकता देना निहित है जो बेरोजगारी एंव अल्प बेरोजगार की अधिक दर वाले क्षेत्रों में अधिक श्रमिकों की खपत वाले श्रमिकों, उपक्षेत्रकों और प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केन्द्रित करने से स्वंय विकास की प्रक्रिया में उत्तपन्न होंगे । प्रमुख गरीबों उन्मूलन कार्यक्रम जो क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराते हैं, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना और रोजगार आश्वासन स्कीम हैं ।शहरी क्षेत्रों में दो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नामत: नेहरू रोजगार योजना और प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रचालित है तथा ये भी रोजगार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार अवसर मुहैया कराने के लिए केन्द्रीय योजना स्कीम के रूप में कार्यान्वित की जा रही है ।

LPG and Telephone Discretionary Quota of MP

1060. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there is a thinking in Government to restore the discretionary quota for LPG and telephones of all the Rajya Sabha MPs; and

(b) if so, the reasons for discrimination in respect of Lok Sabha MPs in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRIMATI RATNAMALA DEHARESHWAR SAVANOOR): (a) and" (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Launching of the Fourth Satellite in INSAT-2 Series

1061. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the fourth satellite inINSAT-2 series had been successfully launched from Korou in French Guyana with the help of a powerful Ariane rocket;

(b) if so, the details in this regard; and

(c) how far it would augment the communication and TV network in India?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): (a) Yes, Sir. The INSAT-2D satellite was launched from Korou, French Guyana on June 4, 1997.

(b) The INSAT-2D satellite is working satisfactorily and is colocated at 74 deg.